SHAKTI®

PUMPING LIFE

**Date: -14/02/2026**

| To,<br>The Secretary,<br>Listing Department<br>National Stock Exchange of India Ltd.<br>Exchange plaza, BKC, Bandra (E)<br>Mumbai-MH 400051. | To,<br>The Secretary,<br>Corporate Relationship Department<br>BSE Limited<br>P. J. Towers, Dalal Street<br>Mumbai- MH 400001. |
|---|---|

**REF :-( ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP**

**Sub:- Newspaper Publications of Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended December 31, 2025.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper publication for Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended December 31, 2025 published on today in the Business Standard in Hindi and The Economic Times in English edition.

Kindly take on record the above information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully
**For Shakti Pumps (India) Limited**

Ravi
Patidar

Digitally signed by Ravi Patidar
DN: c=IN, o=Personal, title=8835,
pseudonym=f5548df080504b6fab66af76e6ae9d7a,
2.5.4.20=098e95d8507c2ee0b78e4884145eebb246409d3498f443b082c47a92a26382c6, postalCode=453331,
st=Madhya Pradesh,
serialNumber=31dde50601e6024b2732ca5972ed69c26147945af389098003ac14a4c85644de, cn=Ravi Patidar
Date: 2026.02.14 13:42:14 +05'30'

**Ravi Patidar**
**Company Secretary**

**SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED**

CIN : L29120MP1995PLC009327 I Web: www.shaktipumps.com I E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com
**Corporate Office** : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020. (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000
**Regd./Factory Address** : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500

वर्ष 18
अंक 301
10 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

शनिवार, 14 फरवरी 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली, **भोपाल**, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

पृष्ठ 10

**वैलेंटाइन डे से पहले बिक्री को रफ्तार**

किरण मजूमदार शॉ पृष्ठ 2

**'बायोफार्मा शक्ति' सकारात्मक कदम**

डॉलर रु. 90.60 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 107.50 ▼ 0.2 रु. | सोना (10 ग्राम) रु. 1,52,153 ▼ 2,874 रु. | सेंसेक्स 82626.80 ▼ 1048.20 | निफ्टी 25471.10 ▼ 336.10 | निफ्टी फ्यूचर्स 25518.80 ▲ 47.70 | ब्रेंट क्रूड 67.50 ▼ 0.50 डॉलर

## एक नज़र

### स्पेक्ट्रम कंपनियों की संपत्ति नहीं : अदालत

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्पेक्ट्रम को कंपनियों की संपत्ति नहीं माना जा सकता और इसे दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। यह ऋणशोधन अक्षमता संपत्तियों से बाहर है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर के पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया और उनके खाते में संपत्ति के तौर पर दिखाया गया स्पेक्ट्रम आईबीसी के तहत कार्रवाई के दायरे में नहीं आ सकता।

### रिलायंस को वेनेजुएला तेल खरीद का लाइसेंस!

रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछले सप्ताह वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद के लिए अमेरिकी सरकार से एक सामान्य लाइसेंस मिला। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली आरआईएल गुजरात में जामनगर कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी विभिन्न प्रकार के भारी कच्चे तेल को प्रॉसेस करने में सक्षम है। पृष्ठ 4

### बांग्लादेश में बीएनपी की सत्ता में वापसी

बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) देश के ऐतिहासिक संसदीय चुनावों के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के बीच शानदार जीत की ओर अग्रसर है और दो दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। खबरों के अनुसार बीएनपी ने 300 सीट वाली संसद में 200 से अधिक सीटें जीत ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में बीएनपी के प्रदर्शन पर पार्टी के शीर्ष नेता तारिक रहमान से बात कर बधाई दी ओर दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। पृष्ठ 10

# एआई से सहमे आईटी शेयर

## सूचकांक में गिरावट बढ़ी, आईटी फर्मों का एमकैप करीब 5 लाख करोड़ रुपये घटा

**समी मोडक**
मुंबई, 13 फरवरी

आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दौर थम नहीं रहा है। निफ्टी आईटी सूचकांक आज कारोबार के दौरान 5.2 फीसदी तक लुढ़क गया था मगर बाद में नुकसान की भरपाई करते हुए 1.44 फीसदी गिरावट के साथ बंद हुआ। अंतिम घंटों में थोड़े सुधार के बावजूद इस हफ्ते आईटी सूचकांक 8.2 फीसदी नुकसान में रहा जो 4 अप्रैल, 2025 के बाद इसका सबसे खराब प्रदर्शन है।

आईटी शेयरों में बिकवाली का असर बेंचमार्क सूचकांकों पर भी पड़ा। सेंसेक्स 1,048 अंक टूटकर 82,627 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 336 अंक गिरकर 25,471 पर बंद हुआ। 1 फरवरी के बाद दोनों सूचकांकों में एक दिन की यह सबसे बड़ी गिरावट है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 7 लाख करोड़ रुपये घटकर 465 लाख करोड़ रुपये रहा।

आईटी सूचकांक की बात करें तो इस साल अभी तक देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 4.7 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। निवेशकों की परिसंपत्ति में यह सबसे तेज गिरावट में से एक है। आईटी शेयरों में तेज गिरावट की मुख्य वजह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में नए विकास से पारंपरिक आईटी कंपनियों की वृद्धि पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती चिंता है।

बिकवाली का यह नया दौर गुरुवार को अमेरिका में प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी गिरावट के बाद शुरू हुआ जिसमें नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स करीब 2 फीसदी तक गिर गया।

स्टार्टअप एंथ्रोपिक के नए एआई टूल से भारत की लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के आईटी उद्योग की भविष्य की वृद्धि की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

जेपी मॉर्गन के एक नोट में कहा गया है कि बाजार का एक हिस्सा इससे परेशान है कि भारतीय आईटी कंपनियां आय वृद्धि के लक्ष्य से चूक सकती हैं क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस दक्षता को देखते हुए ग्राहक अपने खर्च एआई के लिए आवंटित कर रहे हैं।

कारोबार के दौरान इन्फोसिस 7.54 फीसदी तक लुढ़क गया था मगर बाद में थोड़ा संभलते हुए 1.2 फीसदी नुकसान में बंद हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने 6 फीसदी तक टूटने के बाद नुकसान की थोड़ी भरपाई की और कारोबार की समाप्ति पर 2 फीसदी गिरावट पर बंद हुआ। एचसीएल टेक भी 1.2 फीसदी नुकसान में रहा। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण मार्च 2020 के बाद पहली बार 10 लाख करोड़ रुपये से कम रह गया है। बाजार के भागीदारों ने कहा कि तेज गिरावट के बाद कम दाम पर लिवाली से शेयरों में थोड़ा सुधार हुआ।

■ संबंधित समाचार: पृष्ठ 3

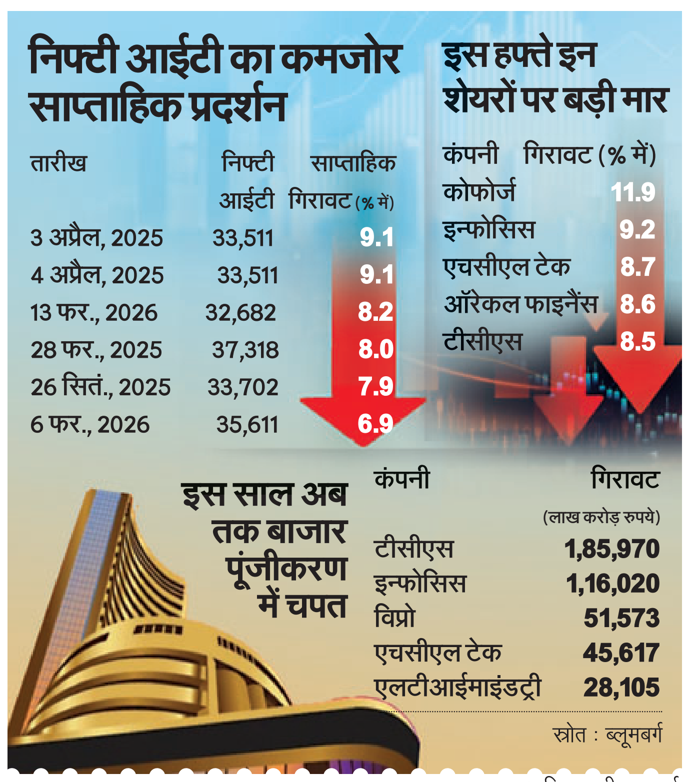

ग्राफिक्स: दीपक शर्मा

# दुरुस्त होगी कैफे-3 के तहत तकनीकी छूट

**दीपक पटेल**
नई दिल्ली, 13 फरवरी

**उत्सर्जन के नए मानदंड**

- कंपनियों को आइडल स्टार्ट-स्टॉप, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और 6-स्पीड ट्रांसमिशन जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए नहीं मिलेगा तकनीक क्रेडिट
- रियायत की कुल सीमा 9 ग्राम/किमी से घटाकर 6 ग्राम/किमी तक सीमित करने पर विचार कर रहा बीईई

**ऊर्जा** दक्षता ब्यूरो (बीईई) उन तकनीकों की फेहरिस्त दुरुस्त करने की योजना बना रहा है जिन्हें कार कंपनियां कैफे-3 मानकों के तहत अपने बेड़े के औसत कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन की गणना करते समय 'ईंधन बचाने वाली तकनीक' की श्रेणी में डाल सकती हैं और 'तकनीकी छूट क्रेडिट' का दावा कर सकती हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है।

अधिकारियों ने कहा कि भारत के यात्री वाहन बाजार में ईंधन बचाने वाली कई तकनीकों का जमकर उपयोग हो रहा है। इनमें करीब 54 फीसदी कारों में आइडल स्टार्ट-स्टॉप (कार कुछ देर खड़ी रहने पर इंजन का खुद बंद हो जाना और क्लच दबाते ही दोबारा स्टार्ट हो जाना) सिस्टम, 47 फीसदी में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (ब्रेक लगाने पर बैटरी चार्ज हो जाना), 63 फीसदी में टायर की हवा पर नजर रखने की प्रणाली और 59 फीसदी में 6-स्पीड या उससे अधिक ट्रांसमिशन होता है। इसलिए प्रस्तावित कैफे-3 मानकों में इन पर तकनीक छूट क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) मानदंड के तहत कार कंपनियों को साल भर में बिके अपने सभी यात्री वाहनों का औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एक सीमा के भीतर रोकना होता है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

**आज का सवाल**

क्या वाकई एआई के विकास से आईटी क्षेत्र पर पड़ेगा प्रतिकूल असर?
www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो Y और यदि न है तो N लिखकर 57007 पर भेजें।

**पिछले सवाल का नतीजा**

ऋण वसूली पर रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से ऋणधारकों को होगी सहूलियत?

हां 76 % | नहीं 24 %

**व्यापार गोष्ठी**

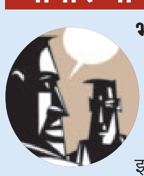

**भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर आपकी राय?**

अपनी राय पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाऊस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें **goshthi@bsmail.in**

अपने विचार आप हमें **www.bshindi.com पर भी भेज सकते हैं**

# सूचीबद्ध व गैरसूचीबद्ध फर्मों को खरीदने के लिए बैंक दे सकेंगे ऋण

**मनोजित साहा**
मुंबई, 13 फरवरी

**भारतीय** रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के अधिग्रहण के लिए ऋण मुहैया कराने की इजाजत दे दी है। मगर ऋण की सीमा कुल मूल्य की 75 फीसदी तय की गई है।

अधिग्रहण के लिए कर्ज देने पर जारी अंतिम नियम में बैंकिंग नियामक ने कहा कि बैंकों को ऐसे निवेश को ऋण सुविधा देनी चाहिए जिसमें लंबी अवधि में अधिग्रहण करने वाली कंपनी के लिए मूल्य सृजित करने की क्षमता हो। केवल अल्पावधि के लाभ या वित्तीय पुनर्गठन के मकसद से ऐसा नहीं करना चाहिए।

बैंक अधिग्रहणकर्ता की एनबीएफसी इकाई या विशेष मकसद वाली इकाई (एसपीवी) के अधिग्रहण के लिए भी धन दे सकते हैं। नियमों के मुताबिक खरीदने वाली कंपनी सूचीबद्ध हो या असूचीबद्ध, उसकी नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ रुपये होनी चाहिए और उसे बीते तीन वित्त वर्ष में लगातार कर बाद मुनाफा हुआ हो। असूचीबद्ध कंपनियों की निवेश ग्रेड रेटिंग बीबीबी- या उससे ऊपर होनी चाहिए। अधिग्रहण खरीद करार की तारीख से 12 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए।

अंतिम नियमों में उस मसौदा प्रस्ताव को हटा दिया गया कि जिसमें कहा गया था कि अधिग्रहण के लिए कर्ज के मामले में बैंक का कुल निवेश उसकी टियर 1 पूंजी के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

अगर अधिग्रहण करने वाली कंपनी के पास लक्षित कंपनी को खरीदने के लिए कर्ज लेने से पहले ही नियंत्रण हो तो पैसे अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए ही दिए जाने चाहिए। आरबीआई ने कहा कि अधिग्रहण करने वाली कंपनी और लक्षित कंपनी में सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं हो।

# महामुकाबले की विज्ञापन दरें आसमान पर

**सुरजीत दास गुप्ता**
नई दिल्ली, 13 फरवरी

**भारत-पाकिस्तान मैच**

- इस रोमांचक टूर्नामेंट के दौरान 10 सेकंड के स्लॉट के लिए करीब 70 लाख रुपये हुआ रेट
- अगर यह मुकाबला नहीं होता तो जिओस्टार की आय को तगड़ा नुकसान होता
- मांग में जबरदस्त उछाल के बावजूद विज्ञापन स्लॉट की उपलब्धता सीमित है

**आईसीसी** पुरुष टी20 विश्व कप में भारत के साथ होने वाले प्रमुख मुकाबले का बहिष्कार करने के अपने फैसले को पाकिस्तान द्वारा वापस लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसका वाणिज्यिक असर दिखने लगा है। दोनों देशों की टीम इस मुकाबले के लिए रविवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आमने-सामने होगी। इसके साथ ही स्पॉट विज्ञापन दरों में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे यह बात पुख्ता होती है कि क्रिकेट के इस महामुकाबले का आर्थिक पक्ष भी बेजोड़ है।

ब्रॉडकास्टर अब इस रोमांचक टूर्नामेंट के दौरान 10 सेकंड के स्लॉट के लिए करीब 70 लाख रुपये मांग रहे हैं। यह रकम 2024 में इसी मुकाबले के लिए वसूलेग गए लगभग 40 लाख रुपये की सर्वाधिक दर के मुकाबले काफी अधिक है। इससे दर्शकों के बीच भारत-पाकिस्तान मुकाबले के प्रति हमेशा रहने वाले आकर्षण का पता चलता है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टूर्नामेंट के दौरान सबसे व्यस्त समय में 10 सेकंड के स्लॉट की स्पॉट दरें आम तौर पर 20 लाख रुपये के आसपास रही हैं। वैश्विक विज्ञापन जगत में सुपर बाउल के लिए अधिक कोटेशन मिलते हैं जहां प्रसारण समय की कीमत 2.2 से 2.8 करोड़ रुपये के बीच होती है। अगर यह मुकाबला नहीं होता तो जिओस्टार की आय को तगड़ा नुकसान होता। उसके पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मीडिया अधिकार हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस साल के वर्ल्ड कप से इस नेटवर्क को करीब 2,000 करोड़ रुपये का विज्ञापन राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। अगर भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होता तो उसे करीब 20 फीसदी तक नुकसान हो सकता था। जहां तक 2024 के टूर्नामेंट की बात है तो विशेषज्ञों के अनुसार, डिज्नी स्टार ने करीब 1,200 करोड़ रुपये का विज्ञापन राजस्व जुटाया था।

मांग में जबरदस्त उछाल के बावजूद विज्ञापन स्लॉट की उपलब्धता सीमित है। रीडिफ्यूजन के चेयरमैन संदीप गोयल ने कहा, 'क्रिकेट में ज्यादातर स्लॉट की बिक्री पैकेज के रूप में की जाती है। चैनल द्वारा स्पॉट बिक्री, खास तौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के लिए मुश्किल से 20-30 फीसदी स्लॉट ही रखा गया होगा। भले ही इससे कमाई अच्छी हो लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है।'

व्यूअरशिप डेटा से विज्ञापनदाताओं की दिलचस्पी के स्तर का पता चलता है। साल 2024 में अकेले भारत-पाकिस्तान मुकाबला भारत में प्लेटफार्मों पर 25.6 करोड़ घंटे देखा गया। डिजिटल पर, ओटीटी और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर पीक कॉन्करेंट व्यूअरशिप लगभग 5.3 करोड़ तक पहुंच गई।

इस साल का मुकाबला अब पक्का हो गया है और इसलिए ब्रॉडकास्टर्स को उम्मीद है कि दर्शकों की तादाद अधिक नहीं तो कम से कम उतनी तो होगी ही।

**FINANCIAL HIGHLIGHTS Q3 FY 25-26**

REVENUE ₹ 551 CR. | EBITDA ₹ 59 CR. | PBT ₹ 42 CR. | PAT ₹ 32 CR. | EPS ₹ 2.57 INR

**STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2025**

(Rs. In Crores, unless otherwise stated)

| S.No | Particulars | Consolidated | | | | | | Standalone | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quarter Ended | | | Nine Months ended | | Year ended | Quarter Ended | | | Nine Months ended | | Year ended |
| | | December 31, 2025 | September 30, 2025 | December 31, 2024 | December 31, 2025 | December 31, 2024 | March 31, 2025 | December 31, 2025 | September 30, 2025 | December 31, 2024 | December 31, 2025 | December 31, 2024 | March 31, 2025 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total Income | 558.69 | 671.89 | 652.73 | 1,854.98 | 1,863.57 | 2,533.33 | 553.25 | 661.72 | 656.88 | 1,827.67 | 1,849.02 | 2,505.04 |
| 2 | Profit before tax | 41.76 | 121.52 | 141.55 | 292.94 | 405.57 | 555.80 | 39.66 | 118.23 | 139.90 | 283.34 | 387.70 | 529.39 |
| 4 | Net Profit/(loss) for the period after tax | 31.70 | 90.71 | 104.05 | 219.25 | 298.14 | 408.37 | 30.05 | 90.20 | 104.67 | 214.66 | 289.23 | 393.63 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | 34.31 | 91.62 | 105.20 | 223.12 | 299.27 | 410.67 | 30.91 | 90.36 | 104.91 | 215.76 | 288.96 | 393.43 |
| 6 | Equity share capital (Face Value: Rs.10/- per share) | 123.40 | 123.40 | 120.21 | 123.40 | 120.21 | 120.21 | 123.40 | 123.40 | 120.21 | 123.40 | 120.21 | 120.21 |
| 7 | Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations (1) Basic | 2.57 | 7.35 | 8.66 | 17.93 | 24.80 | 33.97 | 2.44 | 7.31 | 8.71 | 17.55 | 24.06 | 32.75 |
| | (2) Diluted | 2.57 | 7.34 | 8.66 | 17.92 | 24.80 | 33.97 | 2.43 | 7.30 | 8.71 | 17.54 | 24.06 | 32.74 |

- The Extract of the detailed format of Quarterly Financial Results Filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website: (BSE: https://www.bseindia.com/ and NSE: https://www.nseindia.com/) and the website of the company https://www.shaktipumps.com/ which can also be access by scanning QR code.
- The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 13, 2026
- Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

*Order Book includes domestic & export executable orders as on 13th February 2026

Place : Indore
Date: 13.02.2026

देश का पम्प शक्ति सोलर पम्प
**SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED**

For: Shakti Pumps (India) Limited
SD/-
Dinesh Patidar
Chairman & Whole Time Director
(DIN: 00549552)

CIN : L29120MP1995PLC009327 | Web: www.shaktipumps.com | E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com
**Corporate Office** : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020. (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000
**Regd. Office / Factory Add.** : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500

GOVT DOUBLES LAKHPATI DIDI TARGET, INFRA FUND AT PMO INAUGURATION EVENT

# 'Sewa Teerth' Signals Freedom From Colonial Mindset: Modi

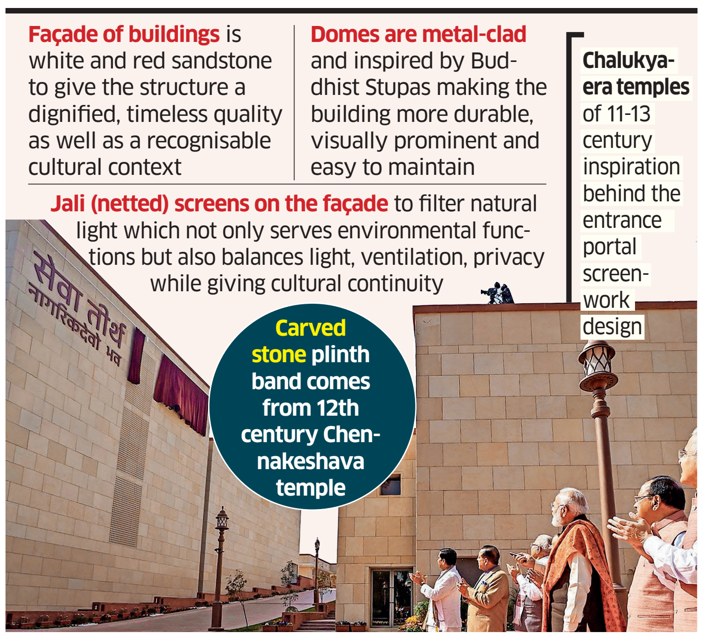


**Our Political Bureau**

**New Delhi:** Prime Minister Narendra Modi underscored on Friday that the new PMO Sewa Teerth is not just a new building complex with a changed nomenclature but one that signifies freedom from the colonial mindset represented by the North and South Blocks as well as emphasis on serving the common people.

"As we move towards Viksit Bharat, it is vital that India sheds every trace of the colonial mindset," he said. The PM underlined that though several important decisions were taken and policies formulated in the North and South Block, these structures were built as symbols of colonial rule and aimed at keeping India in the chains of slavery.

He said the new PMO has been named Sewa Teerth to emphasise that the spirit of service is the soul of India and its true identity. He emphasized that this building will constantly remind everyone that governance means service and responsibility means dedication.

Highlighting the scriptural teaching, "Seva Parmo Dharmah" meaning service is the highest duty, Modi affirmed that this is the vision of the Prime Minister's Office and the government. He stated that Seva Teerth is not just a name but a resolve- a sacred place through service to citizens, a site to carry the pledge of service to fulfilment.

Modi highlighted that as India rides the Reform Express, writing a new chapter in international relations, opening new doors through trade agreements, and moving rapidly towards saturation targets, the new pace of work and renewed confidence in Seva Teerth and Kartavya Bhavans will play a major role in achieving national goals. The Prime Minister underlined that Developed India 2047 is not merely a goal but India's pledge before the world, and therefore every policy and decision made here must be inspired by the continuous spirit of service.

**Developed India 2047 is not merely a goal but India's pledge before the world: PM**

The PM also took some far-reaching decisions on the very first day of the inauguration of Sewa Teerth which include: PM RAHAT Scheme which will give life-saving protection to every citizen, doubling of target of Lakhpati Didis to six crore, Agriculture Infrastructure Fund Doubled to ₹2 lakh crore, Startup India Fund of Funds 2.0 with a corpus of ₹10,000 crore to usher in the next wave of innovation.

## OTHER NEWS OF THE DAY

### 5 Delhi Schools Get Bomb Threat

**New Delhi:** At least five schools in Delhi received bomb threat emails on Friday morning, which were later declared a 'hoax', officials said. The threatening email carried disturbing and provocative content, claiming, "Delhi will become Khalistan and bomb blast will happen at 1.11 pm in schools." The email also claimed that a blast would take place inside Parliament at 2.11 pm, prompting heightened security alerts and coordination among multiple agencies. A similar incident occurred on Monday when more than a dozen schools received bomb threat emails, which also turned out to be a hoax. – PTI

### Security Forces Defuse 14 IEDs

**Bijapur:** Security forces on Friday recovered 14 improvised explosive devices (IEDs) planted by Maoists in a forested area of Chhattisgarh's Bijapur district, police officials said. They also unearthed two Maoist dumps containing explosive materials and other items, the officials added. The recoveries were made during an anti-Naxal operation conducted in Tadpala hills area under Usoor police station limits by personnel of 196th battalion ofCRPF and 204th battalion of CoBRA, an official said. – PTI

TO BE PILOTED BY STATES WITHIN A YEAR

# Deregulation 2.0: Centre Nudges States to Revamp Laws, Drive Business Reforms

**Anubhuti Vishnoi**

**New Delhi:** The NDA-led Centre is preparing to bring in its own series of 'rights'-based bills which are markedly different from those of the UPA era. These bills are focused on ease of doing business and are to be piloted not by the Centre but by state governments, and that too within the year.

Coming up across several states, as part of Deregulation 2.0, are an omnibus Ease of Doing Business Bill (EoDB), a Right to Business Act with an 'Affidavit-Based Clearance System', and a Right to Services Act with automated appeals, **ET** has learnt.

**ET** gathers that the Centre has asked all states to usher in a series of shifts to implement 28 Priority Area reforms as part of Deregulation 2.0. It has also asked state governments to examine every sectoral law, regulation, and circular against six "principles" of deregulation and amend or repeal them accordingly.

The Deregulation Cell of the Cabinet Secretariat, **ET** gathers, will soon share the omnibus EoDB draft bill with all states. The reason: it is assessed that several Priority Areas identified under the Deregulation exercise may require states to approach their legislative assemblies multiple times. It is proposed instead that an omnibus EoDB bill be introduced to facilitate the time-bound implementation of these Priority Areas. To accelerate the "speed of doing business", the Centre has proposed bringing in a Right to Business Act that ushers in an 'Affidavit-Based Clearance System' in place of the NoC regime. Incidentally, Karnataka introduced a similar mechanism in 2020, and Punjab has also incorporated similar elements.

The new Right to Business framework will allow a self-declared Certificate of In-Principle Approval (CIPA) within days for eligible new or expanding MSMEs, along with a prescribed moratorium on inspections. The Act will also establish state and district nodal agencies to streamline approvals, **ET** has learnt.

States have further been asked to re-examine all laws, rules, orders, circulars, notifications, and policies, including municipal-level documents, and assess them on six key principles.

Principle One: Only high-risk activities should require licences/approvals; others should move to self-registration.

Two: All licences should have lifetime validity.

**DEREGULATION CELL**

**The Deregulation Cell of the Cabinet Secretariat is expected to share the omnibus EoDB draft bill with all the states soon**

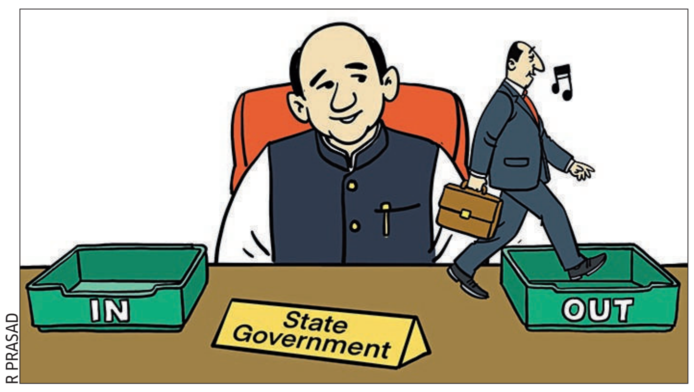


**BUSINESS ENVIRONMENT**

**Deregulation mission aims to align national and state-level reforms to facilitate a 'seamless & enabling business environment'**

Three: Processes should be streamlined and outcome-based, with clear expectations in permits.

Four: Qualified independent third parties may conduct inspections.

Five: All inspections should be risk-based, randomly assigned, transparent, and, where possible, joint or third-party led.

Six: Outdated or redundant laws, rules, and circulars should be repealed or withdrawn. This has been clearly conveyed to all state governments.

The Centre has asked each state to create a comprehensive, sector-wise repository of all such regulations, with last updated dates, and then repeal or amend them in line with the six principles outlined. Similarly, all states have been asked to introduce a Right to Public Services Act — or amend the existing one — to incorporate an online 'auto-escalation appeal system' (similar to Haryana's Auto Appeal System). The idea is that any missed service timeline automatically triggers appeals without any action or application from the business entity. This is to be supported by a public dashboard for real-time monitoring.

Deregulation 2.0 is focused on seven broad categories: land; building and construction; utilities and permissions; environment; education; health; labour; and overarching priorities.

Steered by a task force, led by cabinet secretary TV Somanathan, the compliance-reduction and deregulation mission is aimed at aligning national and state-level reforms to facilitate a "seamless and enabling business environment", and to ensure that these are not one-off exercises but inform a "sustained governance process".

TOP COURT MOOTS SHIFTING MONITORING OF TRIALS TO HC

# SC Directs CBI to File Status Report on Manipur Violence

**Our Political Bureau**

**New Delhi:** The Supreme Court Friday directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to furnish a status report on the multiple cases arising out of violence in Manipur.

A division bench of Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi also underlined the need for transparency, victim participation and effective monitoring of proceedings.

The bench, after hearing submissions from counsels appearing on behalf of victims' families, acknowledged concerns over delays and lack of communication.

On the issue of whether the criminal trials being conducted in Guwahati pursuant to previous directions of the apex court should continue there or the monitoring should now shift closer to Manipur in light of changed circumstances, the bench mooted entrusting the monitoring of trials to the chief justice of the high court.

The bench orally remarked that earlier the situation was different. "That time, this court's decision is perfectly fine. But now that the matters are maturing for trial, and trial might require a very, very close and deep monitoring and supervision, then probably the local judicial authorities are in a better position from that angle". The bench made it clear that it was not expressing any final view and that the final order will be subject to agreement of all stakeholders.

Appearing on behalf of the central government, solicitor general Tushar Mehta submitted that the situation in the state is now peaceful.

**NEED FOR TRANSPARENCY**

**Supreme Court underlined the need for transparency, victim participation & effective monitoring of proceedings**

"People are travelling freely. It is better if the issue is heard in the local environment," Mehta submitted. The bench indicated that subject to consensus amongst all stakeholders monitoring could be entrusted to the chief justice concerned. "Then we can entrust it to the chief justice… we can request to constitute even a special bench to monitor," it observed.

## Convenient Hospitals Limited

**CIN - U85110MP1993PLC007654**

**Registered Office:** Near L.I.G. Square, A.B. Road, Indore, Madhya Pradesh - 452 008, India.

**Telephone No:** 0731-4774444, **Fax No.:** 0731-254 9095, **Email Id:** cs.office@carehospitals.com

**EXTRACT OF UNAUDITED STADALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025**

(₹ in Millons)

| S. No | PARTICULARS | Standalone | | | | | | Consolidated | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quarter Ended | | | Nine months ended | | Year Ended | Quarter Ended | | | Nine months ended | | Year Ended |
| | | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 |
| | | Unaudited | | | | | Audited | Unaudited | | | | | |
| 1 | Total Income from Operations | 553.16 | 541.91 | 502.56 | 1,632.94 | 1,500.08 | 1,991.37 | 553.16 | 541.91 | 502.56 | 1,632.94 | 1,500.08 | 1,991.37 |
| 2 | Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or extraordinary items) | -54.94 | 103.80 | 99.05 | 139.04 | 286.06 | 379.82 | -52.08 | 106.52 | 101.95 | 148.24 | 294.36 | 390.99 |
| 3 | Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or extraordinary items) | -54.94 | 103.80 | 99.05 | 139.04 | 286.06 | 379.82 | -52.08 | 106.52 | 101.95 | 148.24 | 294.36 | 390.99 |
| 4 | Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or extraordinary items) | -47.49 | 78.49 | 86.39 | 97.09 | 228.73 | 274.11 | -45.79 | 80.99 | 88.57 | 103.99 | 238.14 | 285.66 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | -47.82 | 80.10 | 86.39 | 98.37 | 228.73 | 269.59 | -46.12 | 82.60 | 88.57 | 105.27 | 238.14 | 281.14 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 1,325.73 | 1,374.69 | 1,187.32 | 1,325.73 | 1,187.32 | 1,228.12 | 1,514.32 | 1,560.29 | 1,365.52 | 1,514.32 | 1,365.52 | 1,408.52 |
| 8 | Securities Premium Account | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Net worth | 1,420.22 | 1,469.18 | 1,281.81 | 1,420.22 | 1,281.81 | 1,322.61 | 1,608.81 | 1,654.78 | 1,460.00 | 1,608.81 | 1,460.00 | 1,503.01 |
| 10 | Outstanding Debt | 11,965.85 | - | - | 11,965.85 | - | - | 11,965.85 | - | - | 11,965.85 | - | - |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Shares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Debt Equity Ratio | 8.43 | - | - | 8.43 | - | - | 7.44 | - | - | 7.44 | - | - |
| 13 | Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) | - | | | | | | | | | | | |
| | 1. Basic: | -5.03 | 8.31 | 9.14 | 10.28 | 24.21 | 29.01 | -4.85 | 8.57 | 9.37 | 11.01 | 25.20 | 30.23 |
| | 2. Diluted: | -5.03 | 8.31 | 9.14 | 10.28 | 24.21 | 29.01 | -4.85 | 8.57 | 9.37 | 11.01 | 25.20 | 30.23 |
| 14 | Capital Redemption Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Debt Service Coverage Ratio | 0.87 | - | - | 1.64 | - | - | 0.88 | - | - | 1.67 | - | - |
| 17 | Interest Service Coverage Ratio | 0.82 | - | - | 1.47 | - | - | 0.83 | - | - | 1.50 | - | - |

**Notes:**

1. The above standalone unaudited financial results of Convenient Hospitals Limited ("the Company") has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 'Interim Financial Reporting' prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
2. The above standalone unaudited financial results of the Company as reviewed by the Audit Committee on 12 February 2026, has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 February 2026. The results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 has been reviewed by the statutory auditors of the Company. The statutory auditors of the Company have issued an unmodified conclusion in respect of the limited review for the quarter and nine months ended 31 December 2025.
3. The Government of India has consolidated 29 existing labour legislations into a unified framework comprising four labour codes viz the Code on Wages, 2019, the Code, on Social Security, 2020, the Industrial Relations Code, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred to as the "Codes"). The Codes have been made effective from 21 November 2025. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs to enable assessment of the financial impact due to changes in regulations. The incremental impact of these changes, assessed by the Company, on the basis of the information available, consistent with the guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India is not material for the quarter and nine months ended 31 December 2025. The Company continues to monitor the developments pertaining to Labour Codes and will evaluate impact if any on the measurement of liability pertaining to employee benefits.
4. The standalone unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024 and quarter ended 30 September 2025, are presented based on the information complied by the management and have not been subjected to a separate audit or review by the statutory auditors. However, the management has exercised necessary diligence to ensure that the financial results for this period provide true and fair view of the Company affairs.
5. The results for the year ended 31 March 2025 included in the Statement, are extracted from the standalone audited financial statements of the Company which were audited by the previous auditor on which they expressed an unmodified opinion vide their report dated 31 July 2025.
6. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly/ annual financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity at https://www.carehospitals.com/indore/financial-information/quaterly-reports .
7. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/162899f6-a21c-40fd-afac-5975f129a6fd.pdf.

For **Convenient Hospitals Limited**
Sd/-
**Dr. Pawan Kumar**
Managing Director
DIN: 07506347

**Date:** 14/02/2026
**Place:** Indore

**FINANCIAL HIGHLIGHTS Q3 FY 25-26**

| REVENUE | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 551 CR. | ₹ 59 CR. | ₹ 42 CR. | ₹ 32 CR. | ₹ 2.57 INR |

**STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER 2025**

(Rs. In Crores, unless otherwise stated)

| S.No | Particulars | Consolidated | | | | | | Standalone | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quarter Ended | | | Nine Months ended | | Year ended | Quarter Ended | | | Nine Months ended | | Year ended |
| | | December 31, 2025 | September 30, 2025 | December 31, 2024 | December 31, 2025 | December 31, 2024 | March 31, 2025 | December 31, 2025 | September 30, 2025 | December 31, 2024 | December 31, 2025 | December 31, 2024 | March 31, 2025 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1 | Total Income | 558.69 | 671.89 | 652.73 | 1,854.98 | 1,863.57 | 2,533.33 | 553.25 | 661.72 | 656.88 | 1,827.67 | 1,849.02 | 2,505.04 |
| 2 | Profit before tax | 41.76 | 121.52 | 141.55 | 292.94 | 405.57 | 555.80 | 39.66 | 118.23 | 139.90 | 283.34 | 387.70 | 529.39 |
| 4 | Net Profit/(loss) for the period after tax | 31.70 | 90.71 | 104.05 | 219.25 | 298.14 | 408.37 | 30.05 | 90.20 | 104.67 | 214.66 | 289.23 | 393.63 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | 34.31 | 91.62 | 105.20 | 223.12 | 299.27 | 410.67 | 30.91 | 90.36 | 104.91 | 215.76 | 288.96 | 393.43 |
| 6 | Equity share capital (Face Value: Rs.10/- per share) | 123.40 | 123.40 | 120.21 | 123.40 | 120.21 | 120.21 | 123.40 | 123.40 | 120.21 | 123.40 | 120.21 | 120.21 |
| 7 | Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations | | | | | | | | | | | | |
| | (1) Basic | 2.57 | 7.35 | 8.66 | 17.93 | 24.80 | 33.97 | 2.44 | 7.31 | 8.71 | 17.55 | 24.06 | 32.75 |
| | (2) Diluted | 2.57 | 7.34 | 8.66 | 17.92 | 24.80 | 33.97 | 2.43 | 7.30 | 8.71 | 17.54 | 24.06 | 32.74 |

- The Extract of the detailed format of Quarterly Financial Results Filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website: (BSE: https://www.bseindia.com/ and NSE: https://www.nseindia.com/) and the website of the company https://www.shaktipumps.com/ which can also be access by scanning QR code.
- The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 13, 2026
- Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

*Order Book includes domestic & export executable orders as on 13th February 2026

For: Shakti Pumps (India) Limited
SD/-
Dinesh Patidar
Chairman & Whole Time Director
(DIN: 00549552)

Place : Indore
Date: 13.02.2026

देश का पम्प शक्ति सोलर पम्प

**SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED**

CIN : L29120MP1995PLC009327 | Web: www.shaktipumps.com | E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com

**Corporate Office** : Plot No. C-04, Silver Spring, Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opp D Mart, Indore-452020. (M.P.) INDIA. Tel.: +91 731 3635000

**Regd. Office / Factory Add.** : Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur-454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA. Tel.: +91 7292 410500